



दिल्ली बजट: महिलाओं को मिलेंगे हर माह 1 हजार

संजय राय। नई दिल्ली

बिजली हाफ, पानी माफ और महिलाओं को दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा मुहैया कराने के बाद केजरीवाल सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में पूर्ववर्ती शिवराज संघ चौहान सरकार की लाडली योजना से प्रेरणा लेते हुए एस्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार ने सोमवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र से ऊपर वाल सभी महिलाओं के लिए 12000 रुपये की साता देने का ऐलान किया है। योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं को दिल्ली का मतदाता होना अनिवार्य है।

दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत महिलाएं जो किसी अन्य सरकारी योजना के तहत लाभ नहीं ले रही हैं, वे इस योजना के तहत पात्र होंगी। महिला न तो सरकारी कर्मचारी होनी चाहिए और न ही अधिकारी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योजना से दिल्ली में करीब 45 से 50 लाख महिलाओं को फायदा होगा। योजना को लोकसभा चुनाव के बाद लागू किया जाएगा।

मुफ्त योजना लोकसभा चुनाव से पहले आई है जब केजरीवाल की अग्रवाई में आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत लोकसभा सीटों में से चार पर कांग्रेस के गठबंधन सदस्यों के रूप में चुनाव लड़ रही है। इससे पहले विली हाफ, पानी माफ और महिलाओं को दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा योजना पहले से चल रही है।

दिल्ली सरकार के एक आंकड़े से जाता है कि वर्ष 2023-24 में विली चैम्बिंडी के लिए 3250 करोड़ का प्रावधान किया गया, जो वित्त वर्ष 2022-23 में 3161 करोड़ रुपये था। इसके अलावा डीटीसी और डीजीवी को मुफ्त की योजना से

प्रतिवर्ष आंकित किया है।

बजट को राम राज्य से प्रेरित होने का दाव किया गया है। वित्त मंत्री अतिशी ने सोमवार को बजट पेश करते ऐलान किया कि केजरीवाल सरकार राष्ट्रीय राजधानी

विधानसभा में बजट पेश करने जाती वित्त मंत्री अतिशी। फोटो: रंजन डिम्परी

केजरीवाल का डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के बाद आधी आबादी को एक और सौगत

बजट अनुमानित: 2024-25

स्क्रीम/प्रोग्राम/प्रोजेक्ट
39,000 करोड़ रुपये

जलापूर्ति एवं साफ-सफाई
7195 करोड़ (9 प्रतिशत)

हाउसिंग एंड अर्बन
डिवलपमेंट
4395 करोड़
(11 प्रतिशत)

मेडिकल और
सार्वजनिक स्वास्थ्य
3423 करोड़ रुपये
(9 प्रतिशत)

शिक्षा
5476 करोड़
रुपये
(14 प्रतिशत)

अन्य
1423 करोड़
रुपये
(4 प्रतिशत)

कृषि एवं ग्रामीण
विकास व अन्य
1029 करोड़ रुपये
(3 प्रतिशत)

ऊर्जा क्षेत्र
3348 करोड़
रुपये
(9 प्रतिशत)

यातायात
6731 करोड़ रुपये
(17 प्रतिशत)

सामिक
सुरक्षा एवं
कल्याण
5980 करोड़
रुपये
(15 प्रतिशत)

जिसे पिछले साल मार्च में तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अधिकृत कॉलेजिनियों के लिए 6731 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों के लिए 8,241 करोड़ रुपये, दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ रुपये, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और एससी के लिए 16,396 करोड़ रुपये के परिव्यवधारणा के बजट में निर्धारित 9,742 रुपये से कम है।

बजट में परिवहन क्षेत्र के लिए 6731 करोड़ रुपये, स्थानीय निकायों के लिए 8,241 करोड़ रुपये, दिल्ली जल बोर्ड के लिए 7,195 करोड़ रुपये, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और एससी के लिए 16,396 करोड़ रुपये के परिव्यवधारणा के बजट में निर्धारित 9,742 रुपये से कम है।

एससी, औदीसी कल्याण विभाग, परिवहन क्षेत्र के लिए 5702 करोड़ रुपये, अगले वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली सरकार की बस सेवाओं के लिए 3,500 करोड़ करोड़ रुपये, सड़क और फ्लाइओवर के लिए 1,768 करोड़ रुपये, सभी के लिए 664 करोड़ रुपये पोषण संबंधी योजनाएं, अनधिकृत कॉलेजिनियों के लिए 902 करोड़ रुपये, एससीडी को 850 करोड़ रुपये, डीटीसी और बत्सर्टर बसों के बोर्ड में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए 510 करोड़ रुपये और डिवी में दो के लिए 510 करोड़ रुपये। बजट दस्तावेज के अनुसार, स्थानीय व्यापार स्वीकृत बजट अनुमान में अन्य प्रतिबद्ध देनेदारियों को 43,600 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रावधान है।

एससी, औदीसी कल्याण विभाग, परिवहन क्षेत्र के लिए 5702 करोड़ रुपये, अगले वित्तीय वर्ष के लिए 3,500 करोड़ करोड़ रुपये, बिजली क्षेत्र के लिए 3,532 करोड़ रुपये, सड़क और फ्लाइओवर के लिए 1,768 करोड़ रुपये, सभी के लिए 664 करोड़ रुपये पोषण संबंधी योजनाएं, अनधिकृत कॉलेजिनियों के लिए 902 करोड़ रुपये, एससीडी को 850 करोड़ रुपये, डीटीसी और बत्सर्टर बसों के बोर्ड में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए 510 करोड़ रुपये और डिवी में दो के लिए 510 करोड़ रुपये। बजट दस्तावेज के अनुसार, स्थानीय व्यापार स्वीकृत बजट अनुमान में अन्य प्रतिबद्ध देनेदारियों को 43,600 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रावधान है।

एससी, औदीसी कल्याण विभाग, परिवहन क्षेत्र के लिए 5702 करोड़ रुपये, अगले वित्तीय वर्ष के लिए 3,500 करोड़ करोड़ रुपये, बिजली क्षेत्र के लिए 3,532 करोड़ रुपये, सड़क और फ्लाइओवर के लिए 1,768 करोड़ रुपये, सभी के लिए 664 करोड़ रुपये पोषण संबंधी योजनाएं, अनधिकृत कॉलेजिनियों के लिए 902 करोड़ रुपये, एससीडी को 850 करोड़ रुपये, डीटीसी और बत्सर्टर बसों के बोर्ड में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए 510 करोड़ रुपये और डिवी में दो के लिए 510 करोड़ रुपये। बजट दस्तावेज के अनुसार, स्थानीय व्यापार स्वीकृत बजट अनुमान में अन्य प्रतिबद्ध देनेदारियों को 43,600 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रावधान है।

एससी, औदीसी कल्याण विभाग, परिवहन क्षेत्र के लिए 5702 करोड़ रुपये, अगले वित्तीय वर्ष के लिए 3,500 करोड़ करोड़ रुपये, बिजली क्षेत्र के लिए 3,532 करोड़ रुपये, सड़क और फ्लाइओवर के लिए 1,768 करोड़ रुपये, सभी के लिए 664 करोड़ रुपये पोषण संबंधी योजनाएं, अनधिकृत कॉलेजिनियों के लिए 902 करोड़ रुपये, एससीडी को 850 करोड़ रुपये, डीटीसी और बत्सर्टर बसों के बोर्ड में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए 510 करोड़ रुपये और डिवी में दो के लिए 510 करोड़ रुपये। बजट दस्तावेज के अनुसार, स्थानीय व्यापार स्वीकृत बजट अनुमान में अन्य प्रतिबद्ध देनेदारियों को 43,600 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रावधान है।

एससी, औदीसी कल्याण विभाग, परिवहन क्षेत्र के लिए 5702 करोड़ रुपये, अगले वित्तीय वर्ष के लिए 3,500 करोड़ करोड़ रुपये, बिजली क्षेत्र के लिए 3,532 करोड़ रुपये, सड़क और फ्लाइओवर के लिए 1,768 करोड़ रुपये, सभी के लिए 664 करोड़ रुपये पोषण संबंधी योजनाएं, अनधिकृत कॉलेजिनियों के लिए 902 करोड़ रुपये, एससीडी को 850 करोड़ रुपये, डीटीसी और बत्सर्टर बसों के बोर्ड में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए 510 करोड़ रुपये और डिवी में दो के लिए 510 करोड़ रुपये। बजट दस्तावेज के अनुसार, स्थानीय व्यापार स्वीकृत बजट अनुमान में अन्य प्रतिबद्ध देनेदारियों को 43,600 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रावधान है।

एससी, औदीसी कल्याण विभाग, परिवहन क्षेत्र के लिए 5702 करोड़ रुपये, अगले वित्तीय वर्ष के लिए 3,500 करोड़ करोड़ रुपये, बिजली क्षेत्र के लिए 3,532 करोड़ रुपये, सड़क और फ्लाइओवर के लिए 1,768 करोड़ रुपये, सभी के लिए 664 करोड़ रुपये पोषण संबंधी योजनाएं, अनधिकृत कॉलेजिनियों के लिए 902 करोड़ रुपये, एससीडी को 850 करोड़ रुपये, डीटीसी और बत्सर्टर बसों के बोर्ड में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए 510 करोड़ रुपये और डिवी में दो के लिए 510 करोड़ रुपये। बजट दस्तावेज के अनुसार, स्थानीय व्यापार स्वीकृत बजट अनुमान में अन्य प्रतिबद्ध देनेदारियों को 43,600 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रावधान है।

एससी, औदीसी कल्याण विभाग, परिवहन क्षेत्र के लिए 5702 करोड़ रुपये, अगले वित्तीय वर्ष के लिए 3,500 करोड़ करोड़ रुपये, बिजली क्षेत्र के लिए 3,532 करोड़ रुपये, सड़क और फ्लाइओवर के लिए 1,768 करोड़ रुपये, सभी के लिए 664 करोड़ रुपये पोषण संबंधी योजनाएं, अनधिकृत कॉलेजिनियों के लिए 902 करोड़ रुपये, एससीडी को 850 करोड़ रुपये, डीटीसी और बत्सर्टर बसों के बोर्ड में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने के लिए 510 करोड़ रुपये और डिवी में दो के लिए 510 करोड़ रुपये। बजट दस्तावेज के अनुसार, स्थानीय व्यापार स्वीकृत बजट अनुमान में अन्य प्रतिबद्ध देनेदारियों को 43,600 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रावधान है।

एससी, औदीसी कल्याण विभाग, परिवहन क्षेत्र के लिए 5702 करोड़ रुपये, अगले वित्तीय वर्ष के लिए 3,500 करोड़ करोड़ रुपये, बिजली क्षेत्र के लिए 3,532 करोड़ रुपये, सड़क और फ्लाइओवर के लिए 1,7

